गृह राज्यमंत्री राजेन्द्र सिंह यादव की फैक्ट्री पर आयकर विभाग की रेड

कोटपूतली के पाथरेड़ी स्थित राजस्थान फ्लेक्सिबल पैकिंग लिमिटेड फैक्ट्री का मामला

जयपुर, 7 सितम्बर (का.प्र.)। बुधवार सुबह आयकर विभाग की कई टीमों ने देश के चार राज्यों में एक साथ छापेमारी की कार्यवाही को अंजाम दिया और यह कार्यवाही देर शाम तक जारी थी। आयकर विभाग की टीमों ने राजस्थान दिल्ली, उत्तराखंड और महाराष्ट्र में एक साथ छापेमारी की कार्यवाही की है। इस कार्यवाही के तहत राजस्थान के गृह राज्य मंत्री राजेंद्र यादव के कई ठिकानों पर भी आयकर विभाग की टीमों ने एक साथ रेड की। बताया जाता है कि यह छापेमारी मिड-डे मील की सप्लाई में गड़बडी को लेकर हुई है।

राजस्थान के गृह राज्य मंत्री राजेंद्र यादव सहित उनके कई रिश्तेदारों के यहां आयकर विभाग की कार्यवाही एक साथ शुरू हुई। मंत्री के जयपुर स्थित, सिविल लाइन्स के सरकारी आवास, मालवीय नगर स्थित निजी आवास और उनके रिश्तेदारों के यहां सुबह से ही टीमें सर्च में जुट गईं। हालांकि आयकर विभाग की इस कार्यवाही को लेकर मंत्री राजेंद्र यादव का कहना है कि, हमारा मिड डे मील से कोई लेना देना नहीं है।

आयकर विभाग की यह कार्यवाही मंत्री और उनके रिश्तेदारों की कोटपूतली स्थित कंपनी, राजस्थान फ्लेक्सिबल पैकिंग फैक्ट्री सहित अन्य ठिकानों पर हुई है। गृह राज्यमंत्री राजेंद्र यादव इस कंपनी के डायरेक्टर हैं, तो उनका बड़ा बेटा मधुर यादव प्रबंधक है।

बुधवार को सुबह 5.30 बजे मंत्री राजेंद्र यादव और उनके रिश्तेदारों के जयपुर और कोटपूतली स्थित 50 से ज्यादा ठिकानों पर विभाग के अधिकारी पहुंचे उनके साथ बड़ी संख्या में सी.आर.पी.एफ. के जवान थे। यादव कोटपूतली से दूसरी बार कांग्रेस के टिकट पर विधायक बने हैं। कोटपूतली में उनके रिश्तेदारों की एक फैक्ट्री पर भी छापा मारा गया है। बताया जा रहा है कि फैक्ट्री में मिड-डे मील सप्लाई के लिए कट्टे बनाए जाते हैं। आयकर विभाग की ओर कार्रवाई में लगभग 100 वाहनों का भी इस्तेमाल किया गया है। आयकर विभाग की टीमों ने जयपुर में मंत्री के बेटों के घर सहित उनके उत्तराखंड, गुड़गांव स्थित व्यवसायिक और आवासीय ठिकानों पर छापा मारा।

आयकर विभाग ने कोटपूतली में गृह राज्यमंत्री राजेन्द्र सिंह यादव की फैक्ट्री पर छापा मारा।

- **आई.टी. विभाग की टीम सुबह करीब 8 बजे फैक्ट्री पहुंची और दस्तावेज खंगालने में जुटी।**
- **इस कार्रवाई के बाद प्रदेश में सियासी हलचल बढ़ गई।**
- **गृह राज्यमंत्री राजेन्द्र सिंह यादव ने कहा कि, करीब 50 सालों से उनका परिवार कारोबार से जुड़ा है, उन्होंने कार्रवाई को राजनीति द्वेष से प्रेरित बताया।**

जयपुर में राज्यमंत्री राजेन्द्र यादव के सिविल लाइंस स्थित सरकारी आवास और बनीपार्क के निजी आवास सहित मालवीय नगर के ऑफिस में भी इनकम टैक्स के अधिकारी पहुंचे। सूत्रों ने बताया है कि मिड-डे मिल और पौष्टिक आहार बनाने वाले निर्माता, सप्लाई करने वालों, उनके सहयोगियों और परिचितों के यहां रेड की जा रही है।

कोटपूतली के पाथरेड़ी स्थित राजस्थान फ्लेक्सिबल पैकिंग लिमिटेड फैक्ट्री पर भी आयकर विभाग के करीब 10 से 15 अधिकारियों व सीआरपीएफ के जवानों की टीम ने सुबह करीब 8 बजे पहुंच कर रेड की कार्यवाही शुरु की।

जहां कार्रवाई के दौरान फैक्ट्री में बाहरी लोगों सहित मीडिया का प्रवेश भी बंद कर दिया गया। कार्रवाही के बाद प्रदेश में सियासी हलचल भी बढ़ गई है और अफवाहों का बाजार गर्म है।

गृह राज्यमंत्री यादव ने मीडिया से हुई बातचीत में कहा कि वे राजनीति में आने से पूर्व से व्यापार कर रहे हैं। करीब 50 सालों से उनका परिवार कारोबार से जुड़ा हुआ है। आईटी की कार्यवाही को लेकर उन्होंने कहा कि आयकर विभाग का हम पूरा सहयोग करेंगे। यदि आईटी टीम को जांच के दौरान कोई गलत चीज लगती है तो हम उसका जवाब देंगे। उन्होंने यह भी कहा कि जांच के बाद दूध का दूध पानी का पानी हो जायेगा। यादव ने आरोप लगाया कि राजनीतिक द्वेष से प्रेरित होकर यह कार्रवाई की जा रही है। गौरतलब है कि पाथरेड़ी स्थित उक्त फैक्ट्री में केवल प्लास्टिक के कट्टे बनाए जाते हैं जो विभिन्न पैकिंग से जुड़ी फर्मों को सप्लाई किए जाते हैं।

यादव ने कहा कि इनकम टैक्स जांच करे, इसमें मुझे कोई आपत्ति नहीं है। कभी कोई गलत काम नहीं किया, हमने साफ सुथरा काम किया है। इसी के साथ यादव ने कहा कि आयकर की कारवाई में कोई राजनीतिक दुर्भावना होगी, तो वह भी सामने आ जाएगी। आयकर विभाग की कार्यवाही को पॉलिटिकल फंडिंग से जोड़ने पर यादव ने कहा कि पॉलिटिकल फंडिंग से नाम जोड़ना गलत है। हमारा पैकेजिंग का काम है। मिड डे मील से हमारा कोई संबंध नहीं है। हम कट्टे और पैकेजिंग समान बनाते हैं। यहां से कट्टे जाने के बाद उसमें कोई क्या भरता है, इसके लिए हम जिम्मेदार नहीं हैं।

यूनिवर्सिटी के प्रथम वी.सी. की नियुक्ति पर रोचक बहस हुई हाई कोर्ट में

जयपुर, 7 सितम्बर (का.सं.)। राजस्थान हाईकोर्ट में भीमराव अम्बेडकर लॉ यूनिवर्सिटी के वी.सी. की नियुक्ति को चुनौती देने वाली जनहित याचिका पर सुनवाई हुई। इस सुनवाई के दौरान अदालत ने गुरूवार को भी सुनवाई जारी रखने के आदेश दिये।

सुनवाई के दौरान वी.सी. देव स्वरूप की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता कमलाकर शर्मा ने कहा कि केंद्र तथा राज्य सरकार के किसी भी कानून में किसी भी विश्वविद्यालय के प्रथम वी.सी. की नियुक्ति के संबंध में कोई स्पष्ट दिशा निर्देश नहीं है। उन्होंने बताया कि वी.सी. की नियुक्ति के लिये आमतौर पर एक सलेक्शन बोर्ड का गठन किया जाता है, जिसमें पूर्व वी.सी. भी शामिल होते हैं। परंतु जब वी.सी. ही नहीं हो तो बोर्ड का गठन कैसे किया जा सकता है? उन्होंने आगे कहा कि वी.सी. के कार्यक्षेत्र में कॉलेज के बच्चों को पढ़ाना शामिल नहीं होता।

इसीलिये किसी भी वी.सी. के पास उसी क्षेत्र में अकादमिक योग्यता होना आवश्यक नहीं हैं, जिस क्षेत्र में उस कॉलेज के छात्र पढ़ने आये हैं। उन्होंने कहा कि केंद्र या राज्य सरकार के किसी भी कानून में यह वर्णित नहीं है कि वी.सी. की शैक्षणिक योग्यता क्या हो?

उन्होंने आगे कहा कि प्रथम वी.सी. की नियुक्ति "ट्राज़िशनल", यानी अवस्थान्तर, प्रक्रिया है। जब तक कि यूनिवर्सिटी का आधारभूत ढांचा नहीं बना लिया जाता तथा यू.जी.सी. से आवश्यक मान्यता नहीं प्राप्त कर ली जाती।

- **अम्बेडकर लॉ युनिवर्सिटी के वी.सी. की तरफ से वरिष्ठ अधिवक्ता कमलाकर शर्मा ने कहा कि विश्वविद्यालय के प्रथम वी.सी. की नियुक्ति पर कोई स्पष्ट कानून नहीं है।**
- **उन्होंने अदालत को बताया कि वी.सी. की नियुक्ति के लिए सलैक्शन बोर्ड का गठन करना होता है, जिनमें युनिवर्सिटी के मैनेजमैंट के प्रतिनिधि शामिल होते हैं। परन्तु अगर वी.सी. ही नियुक्त नहीं किया गया हो तो बोर्ड का गठन कैसे होगा। इसलिए किसी भी युनिवर्सिटी के प्रथम वी.सी. की नियुक्ति "ट्रांज़िशनल" यानि अवस्थांतर प्रक्रिया है जब तक युनिवर्सिटी का आधारभूत ढांचा नहीं बना लिया जाये और यू.जी.सी. मान्यता प्राप्त नहीं कर ली जाती।**
- **वहीं याचिकाकर्ता की ओर से कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट पहले ही आदेश में पारित कर चुका है कि कॉलेज के प्रिंसिपल की शैक्षणिक योग्यता कॉलेज में पढाए जा रहे विषयों में होनी चाहिए और क्योंकि वी.सी. प्रिंसीपल से ऊंचे पद पर भी होता है, अदालत को यही मापदंड उसकी नियुक्ति पर लागू करना चाहिये।**

याचिकाकर्ता के.बी अग्रवाल की ओर से अधिवक्ता सुनील समदड़िया ने अदालत को बताया कि सुप्रीम कोर्ट पहले ही फैसला दे चुका है कि यूनिवर्सिटी के प्रिंसिपल केवल वही उम्मीदवार हो सकते हैं जिन्होंने उन्हीं विषयों में शैक्षणिक योग्यता प्राप्त की हो जिन विषयों से संबंधित शिक्षा कॉलेज में दी जा रही है। याचिकाकर्ता का यह भी कहना है कि क्योंकि वी.सी. प्रिंसीपल से भी उँचे पद पर होता है इसीलिये अदालत को कानून को ऐसे ही पढ़ना चाहिये कि वी.सी की योग्यता कॉलेज में पढ़ाये जा रहे विषयों से ही संबंधित हो।

अदालत में इस मुद्दे पर गुरूवार को भी बहस जारी रहेगी।

'मक्खन...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

और देश को संगठित रख सकते हैं।

कांग्रेस में यह मज़ाक चल रहा है कि कन्याकुमारी तथा आस-पास के इलाकों में अमूल बटर खत्म हो गया है क्योंकि उन्होंने राहुल गांधी पर भर-भर कर मक्खन लगा दिया है।

गहलोत का एजेण्डा साफ और सीधा है। अगर राहुल कांग्रेस अध्यक्ष बन जाते हैं तो गहलोत के लिये अच्छा रहेगा क्योंकि वे राजस्थान के मुख्यमंत्री बने रहेंगे। और अगर गहलोत पार्टी अध्यक्ष बना दिये जाते हैं तो भी वे राजस्थान के मुख्यमंत्री बने रहना चाहेंगे। यह उनकी पहली एवं अंतिम प्राथमिकता है और इसे हासिल करने के लिये, राहुल गांधी को अमूल मक्खन लगाया जा रहा है।

यह ड्रामा सोनिया गांधी के वापस आ जाने के बाद शुरू होगा, तथा जब जो कुछ गहलोत चाहते हैं, उसे पाने के लिये वे संभवतः एडी-चोटी का जोर लगा देंगे तथा अपने मन्तव्य एवं एजेण्डा को आगे बढ़ाने के लिये गांधी परिवार के प्रति अपनी नज़दीकी का लाभ लेना चाहेंगे।

जो भी है, वे यह सुनिश्चित कर लेना चाहते हैं कि सचिन पायलट मुख्यमंत्री की कुर्सी प्राप्त नहीं कर सकें।

लेकिन सूत्रों का कहना है कि राहुल ने इस बिन्दु पर बड़ा सख्त रूख इख्तियार कर लिया है कि उनके परिवार का कोई भी व्यक्ति कांग्रेस अध्यक्ष नहीं बनेगा तथा माँ सोनिया को भी यह बात माननी ही होगी।

अशोक गहलोत कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिये राहुल गांधी की पसंद हैं और वे ऐसा होते हुआ देखने के लिये वे जी-जान से लगे हुये हैं।

राहुल गांधी चाहते हैं कि गांधी परिवार पार्टी नेतृत्व से अवकाश ले, तथा इस प्रक्रिया में वे अशोक गहलोत की राजस्थान से विदाई का उपयोग सचिन पायलट को राजस्थान का मुख्यमंत्री बनाने के लिये कर सकें, और गहलोत राहुल की इस योजना को पूरा न होने देने में बुरी तरह जुटे हुये हैं।

राजस्थान सरकार से नैशनल ग्रीन ट्रिब्युनल सैन्ट्रल जोन भोपाल ने जवाब मांगा

जयपुर, 7 सितम्बर। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल सेंट्रल जोन भोपाल ने राजस्थान सरकार, राजस्थान पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज गवर्मेंट ऑफ इंडिया एवं सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड मिनिस्ट्री ऑफ़ एनवायनमेंट से जवाब तलब किया है।

नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल सेंट्रल जोन भोपाल ने रामदास बनाम राजस्थान सरकार के मामले में मंगलवार को आदेश पारित किया। इस दौरान ट्रिब्यूनल ने राजस्थान के मुख्य सचिव, और संबंधित बोर्ड और विभागों से पूछा है कि क्यों ना संपूर्ण राजस्थान में ईट भट्टों का संचालन पूरे वर्ष में केवल जनवरी से जून तक ही सीमित कर दिया जाए। वहीं सभी ईट भट्टों में कम प्रदूषण वाली नई टैक्नॉलजी ज़िग-ज़ैग अनिवार्य रुप से अपनाई जाए।

प्रार्थी की अधिवक्ता हरिंदर नील ने बताया कि 2017 में पूरे राजस्थान में 90 हजार और 2019 में 13 लाख लोगों की मृत्यु वायु प्रदूषण की वजह से हुई थी। 2019 में कुल 21.2 प्रतिशत मृत्यु वायु प्रदूषण से हुई थी। यह आंकड़ा राष्ट्रीय स्तर के 18 प्रतिशत से काफी अधिक है। अभी कुछ दिनों पहले ही 2021 की रिपोर्ट में राजस्थान के भिवाड़ी को दुनिया की सबसे प्रदूषित तहसील माना गया था। सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने भी 124 जिलों में से जयपुर, जोधपुर, कोटा, अलवर और उदयपुर को सबसे अधिक प्रदूषित माना है। यह जिले प्रदूषण मापदंडों को पूरा नहीं करते हैं।

- **ट्रिब्युनल ने रामदास बनाम राजस्थान सरकार के मामले में आदेश पारित कर राज्य के मुख्य सचिव और संबंधित बोर्ड और विभागों से पूछा है कि, क्यों ना पूरे प्रदेश में ईंट-भट्टे केवल जनवरी से जून तक ही संचालित किए जाएं।**
- **साथ ही पूछा कि, क्यों न ईंट-भट्टों के लिए कम प्रदूषण वाली नई टैक्नॉलजी "ज़िग-जैग" को अनिवार्य कर दिया जाए।**

इस आदेश से सबसे ज्यादा ईट भट्टे वाले जिले जयपुर, भरतपुर, हनुमानगढ़ और श्रीगंगानगर प्रभावित होंगे। संपूर्ण राजस्थान में कोयले और पेट कोक का ईंट भट्टों में उपयोग होता है, और जिससे सर्वाधिक वायु प्रदूषण होता है। प्रार्थी ने अपना पक्ष रखते हुए यह भी कहा कि, दिल्ली और पंजाब की तरह राजस्थान में ईट भट्टे में कम प्रदूषण फैलाने वाली "ज़िग ज़ैग" टैक्नॉलजी उपयोग में ली जानी चाहिए। इसकी कॉस्ट एफिशिएंसी भी बहुत कम है। अच्छी सांस लेना भी मानवाधिकार अधिकारों में आता है। ईंट भट्टों पर काम करने वाले लोगों को रोका नहीं गया अथवा इनको नई टैक्नॉलजी के अनुरुप नहीं ढाला गया तो राजस्थान भी दिल्ली की तरह प्रदूषित हो जाएगा।

गौरतलब है कि एनजीटी दिल्ली ने पहले ही एनसीआर रीजन के लिए ईट भट्टों का उपयोग केवल मार्च से जून तक कर रहा कर रखा है। यहां वहीं ईट भट्टे ही काम कर सकते हैं जिन्होंने ज़िग-ज़ैग टैक्नॉलजी अपना रखी है। पंजाब सरकार ने भी पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का आदेश माना है।

यहां ईट भट्टों का उपयोग केवल जनवरी से जून तक ही किया जा सकता है। इनमें वे ही भट्टे संचालित हो सकते है जो ज़िग-ज़ैग टैक्नॉलजी का उपयोग करते हैं।

सैन्ट्रल विस्टा एवं कर्तव्य पथ का उद्घाटन आज

नयी दिल्ली, 7 सितंबर (वार्ता)। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी गुरुवार को राजधानी में सेंट्रल विस्टा परियोजना के तहत शाम सात बजे आयोजित कार्यक्रम में कर्तव्य पथ का उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री कार्यालय की बुधवार को जारी एक विज्ञिप्त में कहा गया है कि सत्ता के प्रतीक तत्कालीन राजपथ का नाम बदलकर कर्तव्य पथ करना जन प्रभुत्व और सशक्तीकरण का एक उदाहरण है। इस बीच, राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के प्रतिष्ठित राजपथ को अब कर्तव्य पथ के नाम से जाना जाएगा। नयी दिल्ली नगरपालिका परिषद (एनडीएमसी) की बैठक में बुधवार को इससे संबधित प्रस्ताव पर मुहर लगायी गयी। यह निर्णय आज परिषद की एक विशेष बैठक में लिया गया।

- **प्र.मंत्री मोदी इस मौके पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति का अनावरण भी करेंगे।**

रेलवे अब अपनी जमीन केन्द्र सरकार के अन्य विभागों को लीज़ पर देगा

नयी दिल्ली, 7 सितंबर (वार्ता)। सरकार ने पीएम गति शक्ति अवसंरचना के निर्माण को सुलभ करने के लिए रेलवे की खाली भूमि के उपयोग को लेकर पुरानी नीति को आज बदल दिया जिसके तहत आवंटी को अब भूमि के बाज़ार मूल्य के छह प्रतिशत सालाना की बजाय एक चौथाई यानी डेढ़ प्रतिशत वार्षिक शुल्क देना होगा। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल की आज यहां हुई बैठक में कार्गो संबंधी गतिविधियों, जन उपयोगिताओं और रेलवे के विशेष इस्तेमाल हेतु रेलवे की भूमि नीति को संशोधित करने के रेल मंत्रालय के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की। रेलवे के पास करीब 0.62 लाख हेक्टेयर भूमि उपलब्ध है जिसमें कंटेनर निगम लिमिटेड के पास 26 शहरों में 250 हेक्टेयर भूमि शामिल है।

सरकार का मानना है कि इससे रेलवे को और ज्यादा कार्गो आकर्षित करने में मदद मिलेगी, माल ढुलाई में रेलवे की हिस्सेदारी एवं राजस्व में वृद्धि होगी और इससे इस उद्योग की लॉजिस्टिक्स लागत कम होगी।

- **जमीन प्राप्त करने वाले विभागों को इसके बदले मात्र 1.5 प्रतिशत सालाना वार्षिक शुल्क रेलवे को देना होगा।**

रेलवे की भूमि नीति में बदलाव से सभी पक्षकारों के लिए ज्यादा कार्गो संबंधी सुविधाएं स्थापित करने के रास्ते खुलेंगे और रेलवे के लिए अतिरिक्त कार्गो यातायात एवं माल ढुलाई राजस्व पैदा करने में उनकी भागीदारी की राह भी बनेगी। पीएम गति शक्ति कार्यक्रम में जन उपयोगिताओं के सरल एवं एकीकृत तरीके से विकास में मदद मिलेगी।

नीतीश एवं शरद पवार

नयी दिल्ली, 7 सितम्बर (वार्ता)। बिहार के मुख्यमंत्री एवं जनता दल (यू) के शीर्ष नेता नीतीश कुमार ने राजधानी के अपने प्रवास के दौरान विपक्षी नेताओं के संपर्क अभियान के क्रम में बुधवार को पूर्व केन्द्रीय मंत्री एवं राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के नेता शरद पवार से मुलाकात की और अगले आम चुनाव से पहले विपक्ष की एकजुटता की संभावनाओं पर चर्चा की।

कुमार दिल्ली में पवार के निवास पर गये और वहां करीब 45 मिनट रहे। बैठक के बाद कुमार ने कहा कि विपक्ष मिलकर चुनाव लड़ेगा तो देश के लिए अच्छा रहेगा।

भाजपा के ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

में कमल के खिलने की कोई खास गुंजाइश दिखाई नहीं दे रही। इन विश्लेषकों का कहना है कि भाजपा हिन्दुत्व से जुड़े मुद्दे जितना ज्यादा जोर-शोर से उठायेगी, उसके लिये मतदाताओं को बड़ी संख्या में प्रभावित करने की गुंजाइश उतनी ही कम होती जायेगी, क्योंकि तमिलनाडु के मतदाता जातिगत सोच एवं लिहाज तथा पार्टी के साथ मजबूत जुड़ावों से ज्यादा प्रभावित होते रहे हैं। यह बात सही हो या गलत, लेकिन भाजपा को एक ऐसी पार्टी के रूप में देखा जाता है जो ब्राह्मण एजेण्डा को आगे बढ़ाती है तथा यह चीज अन्य जातियों के लोगों को उससे दूर कर देती है। इसके अलावा, द्रविड-दल भाजपा पर "उत्तर भारत की हिन्दी एक ऐसी पार्टी" तथा एक बाहरी पार्टी होने का ठप्पा लगाने में कामयाब रहे हैं, जो हिन्दी थोपना तथा राज्य को अपने नियंत्रण में लेना चाहती है। द्रविड़ दलों ने तमिलनाडु की जनता के मन में यह चीज पूरी तरह बसा दी है।

तमिलनाडु के भाजपा अध्यक्ष के. अन्ना मलाई की दृढ़ मान्यता है कि हिन्दी के इस भूत के दिन जा चुके हैं। उन्होंने कहा कि पारिवारिक सरोकर, जिसे डी.एम.के. कहा जाता है, के दिन भी लद चुके हैं। लोग परिवर्तन की तलाश में है।

बंधुआ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

जोर देकर कहा कि देश में बंधुआ मजदूर के बहाने एक रैकिट चल रहा है। बैंच ने कई पहलुओं पर सरकार की विस्तृत प्रतिक्रिया का जिक्र करते हुए कहा कि "सरकार जरूरी होने पर कानून के अंतर्गत उपचारात्मक कदम उठाएगी।"

जस्टिस गुप्ता ने बड़ी रूखाई से कहा कि कथित बंधुआ मजदूर वास्तव में बंधुआ नहीं हैं, वे काम के बदले धन लेते हैं लेकिन उसे बीच में छोड़ देते हैं।

उन्होंने टिप्पणी की "उन्हें ईंट भट्टे वाले काम पर रखते हैं। ये लोग पिछड़े क्षेत्रों के हैं। वे पैसा लेकर खा जाते हैं और काम बीच में छोड़ देते हैं। यह एक रैकिट है। ये मजदूर बंधुआ मजदूरों के नाम पर लाभ उठाते हैं।"

'प्राइस कैपिंग की तो गैस व ऑयल सप्लाई पूरी तरह से बंद कर दूंगा'

मॉस्को, 7 सितम्बर। यूक्रेन के खिलाफ जंग छेड़ने वाले रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने अब उन देशों को चेतावनी दी है जो उसके तेल की मूल्य सीमा (प्राइस कैपिंग) करने की तैयारी कर रहे हैं। पुतिन ने कहा है कि जो देश इस योजना में शामिल होंगे उनको रूस की ओर से तेल और गैस की सप्लाई बंद कर दी जाएगी। उन्होंने कहा, ऐस करना बिल्कुल मूर्खतापूर्ण फैसला होगा।

पुतिन ने प्रशांत बंदरगाह शहर व्लादिवोस्तोक में ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम को बताया कि तेल की कीमतों को सीमित करना, जैसा कुछ पश्चिमी देश विचार कर रहे हैं, बिल्कुल मूर्खतापूर्ण निर्णय होगा। उन्होंने कहा, अगर यह हमारे हितों के विपरीत है, तो हम अपने आर्थिक हितों को देखते हुए किसी भी चीज की सप्लाई नहीं करेंगे। कोई गैस नहीं, कोई तेल नहीं, कोई कोयला नहीं, कोई ईंधन तेल नहीं, कुछ भी नहीं। दरअसल, जी7 औद्योगिक शक्तियों ने शुक्रवार को यूक्रेन में मास्को की सैन्य कार्रवाई के लिए धन के एक प्रमुख स्त्रोत को रोकने के लिए, रूसी तेल आयात पर मूल्य कैप को लागू करने की दिशा में तत्काल कदम उठाने का आ ान किया। पुतिन ने कहा, रूस अपने एग्रीमेंट संबंधी दायित्वों को सम्मान करेगा और उम्मीद है कि अन्य देश भी ऐसा ही करेंगे। सर्दियों से पहले यूरोप में बढ़ती ऊर्जा की कीमतों की ओर से इशारा करते हुए, पुतिन ने कहा कि रूस मौजूदा एग्रीमेंटों के अलावा कुछ भी आपूर्ति नहीं करेगा।

अखिलेश...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

केशव प्रसाद मौर्य को मुख्यमंत्री बनाये जाने की अविश्वसनीय पेशकश कर दी है।

विपक्ष को एकजुट करने के अपने मिशन को जारी रखते हुये, बिहार के मुख्यमंत्री ने आज एन.सी.पी. प्रमुख शरद पवार तथा शरद यादव के साथ भी मीटिंग कीं।

इसके अलावा, उन्होंने इस समय अस्वस्थ चल रहे सपा-संस्थापक मुलायम सिंह यादव से भी भेंट की।

अखिलेश यादव ने मंगलवार को यह पेशकश कर दी कि अगर केशव प्रसाद मौर्य 100 विधायकों को साथ लेकर भाजपा से संबंध-विच्छेद कर लें तो वे मुख्यमंत्री पद की उम्मीदवारी के लिये मौर्य का समर्थन कर देंगे। यह प्रस्ताव रखते हुये, अखिलेश उत्तर प्रदेश भाजपा में अंदरूनी लड़ाई की स्थिति पैदा करने की रूपरेखा बना रहे हैं, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि मौर्य को शाह का आशीर्वाद प्राप्त है तथा उनकी गिनती योगी आदित्यनाथ के पसंदीदा लोगों में नहीं होती है।

रूस/चीन व अमेरिका के तनाव ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

मुखपत्र बन गया है जो कि यूक्रेन वॉर पर पुतिन का पक्ष ही प्रस्तुत करता है।

बीजिंग विंटर ओलम्पिक्स से पहले और पुतिन द्वारा यूक्रेन में रुस की सैन्य घुसपैठ की अनुमति से पूर्व शी एवं पुतिन बीजिंग में मिले थे तथा दोनों ने दोनों देशों के बीच "लिमिटलैस" (असीमित) दोस्ती की घोषणा की गई थी।

भारत इन दोनों मित्रों के बीच फंस गया है बिल्कुल "एलिस इन वंडरलैंड" की तरह भारत को भी रुस और पश्चिम के साथ संबंधों में संतुलन बनाना है, चीन के साथ बढ़ते टकराव के संदर्भ में।

जहां भारत के रुस के साथ अच्छे सम्बंध हैं लेकिन चीन भारत से लगती सीमा पर समस्याएं खड़ी करता रहता है। ऐसे ही एक सैन्य टकराव में भारत के 21 जवान शहीद हो गए थे।

दोनों निरंकुश तंत्र रुस और चीन एक साथ आ गए हैं और दोनों के हित एक जैसे हैं क्योंकि दोनों ही स्थापित कूटनीतिक प्रक्रिया को दरकिनार कर रहे हैं और सैन्य हस्तक्षेप से समस्याएं सुलझाना चाहते हैं।

जहां रुस ने यूक्रेन में घुसपैठ की है वहीं चीन भी ताईवान को ताकत के बल पर कब्जा करने की धमकी दे रहा है।

- **अब तक तो भारत चीन/रूस व अमेरिका के तनावों के बीच बहुत चतुराई से अपना काम चलाता रहा है, पर चीन/रूस और आक्रामक हुए, तो यह संतुलन बिठाना और कठिन हो जायेगा।**

इसके अलावा चीन दक्षिण चीन सागर के बड़े हिस्से पर भी दावा कर रहा है और इस क्षेत्र को अन्तर्राष्ट्रीय शिपिंग चैनल के रुप में प्रयुक्त करने से रोक रहा है, जहां से वैश्विक व्यापार होता है।

इससे भी बुरी बात है कि चीन सीमा पर भी तनाव पैदा कर रहा है और सीमा पर स्थित कई क्षेत्रों को अपना बता रहा है। चीन हिंद महासागर में अपने बेस बनाकर भारत को घेर रहा है। इसने हॉर्न ऑफ अफ्रीका में नौसैनिक बेस बनाया है। जहां से यह हिंद महासागर में शक्ति प्रदर्शन कर सकता है।

इसके अलावा चीन ने श्रीलंका में भी एक प्रमुख बंदरगाह "हम्बनटोटा" पर कब्जा कर लिया है, जहां हाल ही में इसने कथित तौर पर एक रिसर्च नौका भेजी थी जो भारतीय सैटेलाइट को ट्रैक कर सकती है।

चीन के साथ इस टकराव पूर्ण रिश्ते में भारत ने अमेरिका से काफी सहयोग व समर्थन लिया है इसने भारत तो उसके पारम्परिक मित्र रूस से दूर कर दिया है।

रूस और अमेरिका के बढ़ते टकराव के बाद भी भारत ने दोनों देशों के बीच चतुराई से संतुलन बनाया है। भारत ने पश्चिम के प्रतिबंधों को ठुकरा कर रूस से तेल खरीदना जारी रखा साथ ही चीन के साथ लगती सीमा पर तैनात करने के लिए अमेरिका से हथियार खरीदे।

इसके अलावा भारत चीन के आक्रामक इरादों को रोकने के लिए बने उदार लोकतांत्रिक देशों के गठबंधन का भी महत्वपूर्ण भाग है। इण्डो पैसेफिक क्षेत्र में अन्तर्राष्ट्रीय संबंधों में नौसैनिक युद्ध व क्षमता महत्वपूर्ण भार के रूप में उभरी है और एशिया में चीन के खिलाफ अमेरिका ने भारत को समर्थन देना शुरू कर दिया है।

आयकर विभाग ने गैर...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

चुनावी पैनल ने यह भी घोषणा की थी कि वह 21 सौ से अधिक ऐसी संस्थाओं के खिलाफ कार्रवाई कर रहा है, जिन्हें धन के अंशदानों की प्रतिष्ठियां करने सहित चुनाव के नियम-कायदों का उल्लंघन करने के कारण पंजीकृत किन्तु गैर-मान्यता प्राप्त राजनीतिक पार्टियों के रूप में वर्गीकृत किया गया है। इन संस्थाओं ने अपने कार्यालयों के पते और पदाधिकारियों के नाम तक अपडेट नहीं किए हैं। उसने कहा था कि इनमें से कुछ पार्टियां "गंभीर" वित्तीय अनियमितताओं में संलग्न हैं।

चुनावी पैनल के अनुसार उसने राज्यों के मुख्य निर्वाचन अधिकारियों की रिपोर्ट के बाद कार्रवाई की। इन अधिकारियों ने रिपोर्ट दी थी कि सत्यापन के दौरान इन पार्टियों को या तो अस्तित्वहीन पाया गया था जब उनके पते और संवाद के विवरणों के सत्यापन के लिए संबंधित प्राधिकरण द्वारा उन्हें पत्र भेजे गए तो वे पुनः लौट आए। डाक विभाग ने भी इन पत्रों को अनडिलीवर्ड माना है। चुनाव आयोग ने इसके बाद इन पार्टियों को सिम्बल्स ऑर्डर (1968) के अन्तर्गत मिले कई लाभों को वापस लेने का निर्णय लिया। इन लाभों में कॉमन इलैकशन सिम्बल का आवंटन भी शामिल है। गत जून माह में जारी एक बयान में चुनावी पैनल ने कहा था कि निर्णय से व्यथित कोईभी रजिस्टर्ड अनरिकग्नाईज़ड पॉलीटिकल पार्टी (आर.यू.पी.पी.) 30 दिनों के भीतर संबंधित मुख्य निर्वाचन अधिकारी के समक्ष उपस्थित हो सकती है, लेकिन उसे अपने साथ अपने अस्तित्व के सभी प्रमाण, वार्षिक ऑडिट अकाउन्ट्स, अंशदान एवं व्यय रिपोर्ट और पदाधिकारियों की अपडेट लिस्ट लानी होगी।

चुनावी पैनल के सूत्रों ने कहा था कि ऐसी पार्टियों के विक्षेप विवरण सार्वजनिक रूप से उपलब्ध हैं जिन्होंने फण्ड्स और डोनेशन्स का खुलासा करने में नियम कानूनों का उल्लंघन किया है।

चुनाव आयोग ने गंभीर वित्तीय अनियमितताओं में शामिल ऐसी तीन पार्टियों के विरूद्ध आवश्यक कानूनी व आपराधिक कार्वाही करने के लिए बाद में राजस्व विभाग को एक रेफरेंस भेजा। राजस्व विभाग केन्द्रीय वित्त मंत्रालय के अधीन कार्यरत हैं।

राजस्व विभाग ने बाद में इस रिपोर्ट को कर विभाग की प्रशासनिक इकाई सैन्ट्रल बोर्ड ऑफ डायरैक्टर टैक्सेस (सी.बी.डी.टी.) को भेजा। बुधवार की कार्रवाई में आयकर विभाग की विभिन्न जांच इकाईयों ने भाग लिया।

अधिकारिक डेटा के अनुसार भारत में करीब 2 हजार 8 सौ पंजीकृत गैर मान्यता प्राप्त राजनीतिक पार्टियां है। चुनावी पैनल सरकार पर दबाव बनाता रहा है कि उसे इन राजनीतिक पार्टियों का पंजीकरण रद्द करने की अनुमति दी जाए।

राष्ट्रदूत (एच.यू.एफ.) के लिए मुद्रक एवं प्रकाशक सोमेश शर्मा द्वारा वतन प्रेस, सुधर्मा, एम.आई.रोड़, जयपुर एवं सुधर्मा-II, लालकोठी शॉपिंग सेंटर, टोंक रोड़, जयपुर से मुद्रित एवं प्रकाशित। संपादक:- राजेश शर्मा । आर.एन.आई. नं. 3641/57, ई-मेल-rastrdut@gmail.com कोटा कार्यालय:-पलायथा हाउस, छत्रपति शिवाजी मार्ग, कोटा। फोन:2386031, 2386032, फैक्स:0744-2386033 बीकानेर कार्यालय:-कुंम्भाना हाउस, हनुमान हत्था, बीकानेर। फोन:2200660, फैक्स: 0151-2527371 उदयपुर कार्यालय:-आयड, मेन रोड आयड, उदयपुर। फोन: 2413092, 2418945, फैक्स: 0294-2410146 अजमेर कार्यालय:-घूघरा घाटी, जयपुर रोड,अजमेर। फोन: 2627612, फैक्स:0145-2624665 जालोर कार्यालय :- जी 1/63, इन्डस्ट्रीयल एरिया, फेस प्रथम, जालोर। फोन: 226422, 226423, फैक्स: 02973-226424 हिण्डौनसिटी कार्यालय :- जी -1-201, रीको औद्योगिक क्षेत्र, हिण्डौनसिटी। फोन: 230200, 230400, फैक्स: 07469-230600 चूरू कार्यालय: एच-150, रीको औद्योगिक क्षेत्र, चूरू, फोन: 256906, 256907, फैक्स:01562-256908